THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHA-NAN)4 (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आयकर और सीमा शुल्क कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

178.**श्री मुनव्वहर हसन**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर और सीमा शुल्क कर्मचारियों द्वारा देशव्यापी हड़ताल के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार और संघ के बीच कोई समझौता हो गया हैं;

(ग) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) इस हड़ताल की वजह से कुल कितनी राजस्व हानि हुई हैं;और

(ड़) सरकार भविष्य में ऐसी हड़ताल की रोकथाम के लिए और राजस्व की हानि की पूर्ति के लिए क्या-क्या कदम उठाने जा रही हैं?

वित्त मंत्रालय (बैंकिग,राजस्व तथा बीमा में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर.जनार्दनन): (क) आयकर,सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समूह "ख" और "ग" के कार्यकारी अधिकारी बेहतर वेतनमानों और सेवा शर्तो में कुछ सुधार के लिए अपनी मांगों के समर्थन में दिनांक 10.11.98 से 12.11.98 तक हड़ताल पर गए थे।

(ख) जी,नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) शून्य।

(ड़) सद् भावनापूर्ण और सकारात्मक कार्यकारी संबंध बनाने के उद्देश्य से कर्मचारियों के संघों के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर बातचीत की जा रही हैं।

Incentives to the PAN Holders

179. SHRI RAGHAVJI:
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some" incentives were announced at the time of announcing the Permanent Account Number (PAN) Scheme;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether these incentives have been extended to the PAN holdres; and

(d) whether those who could not apply for PAN by 31st October, 1998 can apply for the same now, and if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHA-NAN): (a) and (b) The Government had announced to introduce a scheme called 'SAMMAN' to demonstrate society's recognition of the important contribution made by tax payers to the national cause. The scheme would outline facilities and recognition to be conferred on the tax payers. A Committee was set up to give a concrete shape to the Samman scheme. The Committee has since submitted its report for the consideration of the Government.

(c) The incentives propsoed in the report of the Committee after they are accepted and finalised by the Government shall be availed by the taxpayers who would also be PAN holders as taxpayers are statutorily required to apply for PAN.

(d) Tax payers who were required to file the application for allotment of PAN by a specified date and have not done so can file the application later on.

मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज़ का भारत की विकास दर संबंधी मूल्यांकर

180.**श्री बरजिन्दर सिंह**:

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका स्थित मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज़ ने मूल्यांकन किया है कि वर्ष 1998-99 के दौरान भारत में वार्षिक विकास दर चार प्रतिशत के आसपास होगी ;

(ख) यदि हां,तो सरकार ने मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज़ की टिप्पणी पर विचार करके तथ्यों का पता लगाया है ;

(ग) यदि हां,तो सरकार का वार्षिक विकास दर के संबंध में क्या मूल्यांकर है;और

(घ) सरकारी आकलन के मूल्यांकर के आधार क्या –क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) से (घ) मैसर्स मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज़ ने अपने हाल ही के प्रभुसत्ता सम्पन्न कर निर्धारण पुनरीक्षा अभ्यास से अर्थ व्यवस्था की अभिवृद्वि की संभावना को शामिल करते हुए अनेक पैरामीटरों को हिसाब में लिया है। सरकार मैसर्स मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज़ द्वारा लगाए गए अभिवृद्वि अनुमान से सहमत नहीं है और यह आशा करती है कि वर्ष 1998-99 में सकल घरेलू उत्पाद की अभिवृद्वि दर लगभग 6 प्रतिशत रहेगी।

Reorientation of Banking Service

181. SHRI KRISHNA KUMAR BIR LA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Associated Chambers of Commerce and Industry of India has recently recommended to Government to modernise and reorient banking services to customer needs;

(b) if so, whether Government have drawn up any plans for the revitalising of PSU banks in the country; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING REVENUE & INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHA-NAN): (a) to (c) Government are aware of the recommendations of the Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) regarding reforms in the Banking sector. The process of reform is a continuing process and the suggestions made by the ASSOCHAM along with suggestions received from other sources constitute inputs in the engoing efforts to undertake Banking Sector Reforms.

बैंकिंग सेवा भती बोर्ड

182.**श्री रमा शंकर कौशिक**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बैंकिग सेवा भर्ती बोर्ड को भग करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां,तो कब तक और यदि नही,तो ऐसे बोर्डो की क्या उपयोगिता हैं;

(ग) इन सोलह बोर्डो पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही हैं;और

(घ) पिछले तीन वर्षो के दौरान इन बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डो द्वारा कितने व्यक्तियों का चयन किया गया ?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग,राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर.जनार्दनन) : (क) जी,नहीं।

(ख) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड सरकारी क्षेत्र के बैकों और साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए लिपिक संवर्ग और साथ ही अधिकारी संवर्ग में कर्मचारियों की भर्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं

(ग) इन बोर्डो पर वर्ष 1997-98 में किया गया खर्च 22.39 करोड़ रूपए था। इन बोर्डो द्वारा सृजित आय 9.23 करोड़ रू.थीं। इस प्रकार 13.16 करोड़ रूपए का घाटा सरकारी क्षेत्र के संबंधित समन्वयकर्त्ता बैंकों को पूरा करना था

(घ) इन बैंकों ने पिछले तीन वर्षो के दौरान विभिन्न पदों के लिए विविध बैंकों को 14,246 अभ्यर्थी आवंटित किए थे।

Non-quotation of Companies in Stock Exchanges

183. SHRI S. AGNIRAJ: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is fact that many companies after calling for Public Issues have not been quoted in stock exchanges since 1994;

(b) if so, the details of such defaulting companies;

(c) what steps are being taken to help the investors to recover their money from such companies; and

(d) when this scheme is likely to be implemented?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) As per information furnished by SEBI, 1210 companies came out with